राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समस्याएँ एवं समाधान

डॉ० मंजू शर्मा

सहायक आचार्या,

सनराईज कॉलेज ऑफ एजूकेशन, सोनीपत

Email Id: drmanjusharma@gmail.com

साराश:-

आज के तत्कालीन युग में परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे है। समाज और राष्ट्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा हमारी मूलभूत आवश्यकता है। भारत एक विकसित देश बनने के साथ-साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय संविधान के लागू होते ही शिक्षा में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए गए। माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1968 में देश की पहली शिक्षा नीति बनाई गई। शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुधारों की मॉग के आधार पर 1986 में दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की देश की तीसरी शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य शिक्षा की गुणवता के उच्चतर स्तर को बनाए रखना है। लेकिन कोविड-19 के कारण शिक्षा व्यवस्था में अनेक कमियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र के द्वारा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में उपस्थित समस्याओं तथा उनका समाधान कैसे किया जाए के बारे में बताया गया है जिससे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने में सहायता मिल सके।

सांकेतिक शब्द: शिक्षा, समस्याएँ, समाधान

परिचय:-

भारत की स्वतन्त्रता के बाद वर्ष 1968 में कोठारी आयोग की सिफारिशों पर पहली ww राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। वर्ष 1986 में देश की शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों के साथ शिक्षा की पहुँच को मजबूत करने और शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त असमानताओं को दूर करने हेतु दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्व इसरो (ISRO) प्रमुख डॉ० के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा की गुणवता में सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के योग्य बनाना है।

शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों ?

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता होना।

- शिक्षा की गुणवता को बढाने, नवाचार और अनुसंधान को बढावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता होना।
- भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सम्बन्धित मुख्य तथ्य :-

- **वोकेशनल ट्रेनिंग को महत्व दिया जाना :-** राष्ट्रीय शिक्षा के अन्तर्गत 2025 तक वोकेशनल पढाई करने वालों का प्रतिशत 50 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है जो अभी तक 5 से भी कम है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को वोकेशनल ट्रेनिग दी जाएगी जिसमें उन्हें बागवानी, मिटटी के बर्तन बनाना बिजली का काम आदि सिखाया जाएगा। इससे हमारे विकास कौशलों में वृद्धि होगी।

- **एम. फिल को समाप्त करना और बी.एड प्रोग्राम 4 साल का करना :-** राष्ट्रीय शिक्षा 2020 में एम.फिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। एम.फिल स्तर पर शोध कार्य लघु स्तर पर किया जाता है जिससे शोध कार्य के परिणाम कई बार अधूरे रह जाते है। साथ ही अब बी.एड प्रोग्राम 2 वर्ष से बढाकर 4 वर्ष का कर दिया गया है।

- **भारतीय भाषाओं का बढ़ावा :-** राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5 तक अंग्रेजी की अनिवार्यता हटा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने की सुविधा दी है, क्योंकि एक विद्यार्थी जितना अपनी मातृभाषा में सिख सकता है अन्य किसी भाषा में नहीं सिख सकता।

- **विदेशी भाषा को भी शामिल करना :-** विद्यार्थियों को अब माध्यमिक स्तर से विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएगी। इस तरह से छात्रों को कहीं भी किसी भी क्षेत्रों में पिछड़ने से बचाया जा सकता है।

- **किसी एक विषय में चुनाव की बाध्यता खत्म :-** अब से स्कूल व कॉलेज में किसी भी एक विषय को चुनने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। छात्र अपने विषय अपनी पसंद से चुन सकेंगें। सही निर्देशन न मिलने के कारण विद्यार्थियों को विषयों का चुनाव करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पडता था।

- **शिक्षा के साथ कौशल विकास पर भी ध्यान :-** नई राष्ट्रीय शिक्षा के अन्तर्गत अब छात्रों को शिक्षा नीति के साथ कौशल पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्हें शुरूआती कक्षाओं से ही संगीत, नृत्य, योग, मूर्तिकला आदि अन्य कलाओं में भी पारंगत किया जाएगा।

- **मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री की सुविधा :-** नई नीति के तहत अब अगर पढाई में किसी छात्र को किसी कारणवश ब्रेक लेना www पडता है तो वो बाद में भी अपनी पढाई पूरी कर सकता है। साथ ही छात्र को उसके पढे हुए अवधि के अनुसार सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री आदि प्रदान किये जायंगे जिसका लाभ विद्यार्थी अपने भविष्य को सफल बनाने में ले सकता हैं।

- **अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट :-** अब विद्यार्थियों से सम्बन्धित जानकारियाँ, डाक्यूमेंटस व अंक आदि को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा। जिसे बाद में डिग्री प्रदान करते वक्त इस्तेमाल किया www जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सम्बन्धित समस्याएँ :-

- **महँगी शिक्षा :-** राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है, विभिन्न शिक्षाविदो का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महँगी होने की सम्भावना है, परिणाम स्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

- **शिक्षको का पलायन :-** विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारत के दक्ष शिक्षक भी इन विश्वविद्यालयों में अध्यापन हेतु पलायन कर सकते है।

- **शिक्षा का संस्कृतिकरण :-** दक्षिण भारतीय राज्यों का आरोप है कि 'त्रि-भाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।

- **संसद की अवहेलना :-** विपक्ष का आरोप है कि भारतीय शिक्षा की दशा और दिशा तय करने वाली इन नीति को अनुमति देने में संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। पूर्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 भी संसद के द्वारा लागू की गई थी।

- **मानव संसाधन का अभाव :-** वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारम्भिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन www में व्यवहारिक समस्याएँ है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, के सफल कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी, जिसमें केन्द्र व राज्यों के बीच समन्वय तथा सहयोग, नए कानूनों का निर्माण या मौजूदा कानूनों में संशोधन सहित अन्य विधायी हस्तक्षेप, वित्तीय, संसाधनों की वृद्धि और नियामकीय सुधार आदि शामिल है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में संकल नामांकन अनुपात दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में देश में लगभग 1000 विश्वविद्यालय है। ऐसे में इतने अधिक छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये बहुत से नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी होगी।

- वर्तमान में शिक्षा तंत्र और अन्य संसाधनों के मामले में देश के अलग-अलग राज्यों की स्थिति में भारी अंतर है, वर्ष 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्कूली शिक्षा गुणवता सूचकांक में देश भर में स्कूली शिक्षा

की गुणवता में भारी अंतर पाया गया है, ऐसे में छात्रों के लिए इन परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को डालना कठिन होगा।

- वर्ष 1968 में जारी की गई पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पर केन्द्रीय बजट का 6 व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अगली सभी नीतियों में दोहराया गया, परन्तु अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है, जो कि सरकार की नीतिगत असफलता और कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है।

- कोविड-19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बीच राज्यों के लिये इन सुधारों को लागू करने के लिए आवश्यक धन एकत्र करना बहुत ही कठिन होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से सम्बन्धित समाधान :-

1. उच्च शिक्षा सुधार हेतु विशेष कार्यबल की स्थापना :-

- प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु सहयोग के लिए एक विशेष कार्य बल । थ्वतबगद्ध की स्थापना की जानी चाहिए।
- प्रधानमंत्री का यह कार्य बल एक सलाहकारी बल हो सकता है जिसमें सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- यह कार्यबल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को समझने और एक निश्चित जवाबदेही के साथ समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री की सहायता करेगा।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु स्थायी समिति

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन हेतु एक स्थायी समिति की स्थापना बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है।
- इस समिति की अध्यक्षता केन्द्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों के कुलपति, निर्देशक इसमें समिति के सदस्य होंगे।
- यह समिति उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के दौरा आने वाली चुनौतियों को दूर करने में सहायता करेगी।

3. राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री परिषद :-

- इस परिषद में सभी राज्यों और केन्द्रित शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे तथा परिषद की अध्यक्षता केन्द्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी।
- साथ ही यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के मुद्दों पर चर्चा तथा समस्याओं के निवारण के साथ राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।

4. इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में सुधार :-

- वर्तमान में इस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के दृष्टिकोण को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यान्वयन योजना के सथ एकीकृत करने की आवश्यकता हैं। इस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को अधिक स्वतन्त्रता, स्वायतता देने के साथ संसाधनों के मामलें में सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
- इसके माध्यम से भारत के विश्वविद्यालयों को वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिग में अपनी स्थिति में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष :-

अतः किसी भी देश की प्रगति के साथ-साथ उसके नागरिको के सर्वांगीण www www विकास के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण आधार माना गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एक अच्छी नीति है क्योंकि इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी और 2030 संवत विकास लक्ष्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप, समग्र, लचीला, बहुविषयक बनाना है।

सन्दर्भ :- 1. प्रारूप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

2. Hindi Careindia.com
3. Drishtiias.com
4. www.dhyeyaias.com
5. www.gyanniram.com